GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

बजट 2024-25

मनोहर लाल

मुख्य मन्त्री, हरियाणा

वित्त मन्त्री के रूप में

बजट भाषण, 23 फरवरी, 2024

FINANCE DEPARTMENT, HARYANA

वित्त विभाग, हरियाणा

माननीय अध्यक्ष महोदय!

मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2024–25 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

1. माननीय अध्यक्ष महोदय! इस सरकार का लगातार पांचवां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है।

2. लगभग पांच सौ वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणावासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राम राज्य की भावना के प्रसार से सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात होगा और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में मदद मिलेगी।

3. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अटल नक्षत्र की तरह चमक रहा है। भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और हाल ही में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।

4. पिछले वर्षों में हरियाणा ने अतुलनीय प्रगति की है, जो कि नए और जीवंत राज्य के उदय तथा एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी– आधारित शासन प्रणाली के साक्षी हैं। सरकार ने सामाजिक और भौगोलिक समावेशिता के लिए काम किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों और राज्य के सभी क्षेत्रों का बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के विकास किया जा रहा है।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय! वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के हैं। इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य–योजनाओं से रखनी होगी।

वृहद आर्थिक मानदंड

6. माननीय अध्यक्ष महोदय! वर्ष 2014–15 से वर्ष 2023–24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2011–12 के मूल्यों) पर 6.1 प्रतिशत रही है, जो वर्ष 2014–15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023–24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक है।

7. हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023–24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

8. वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014–15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023–24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है। यह वृद्धि 114 प्रतिशत है। जबकि, हरियाणा में यह वर्ष 2014–15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023–24 में

बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना

9. वर्ष 2023–24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2023–24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित है।

10. वर्ष 2023–24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

बजट 2024–25

11. माननीय अध्यक्ष महोदय! मैं वर्ष 2024–25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो वर्ष 2023–24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत है। इसके अलावा, वर्ष 2024–25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए, कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

12. बजट अनुमान 2024–25 में, उत्साहजनक राजस्व प्राप्तियों और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। मैने 1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर

राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर–कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जी.एस.टी, वैट, आबकारी और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये है। इसके अलावा मैने 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है।

राजकोषीय मानक

13. माननीय अध्यक्ष महोदय! मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023–24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 2024–25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर है।

14. सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023–24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है। वर्ष 2024–25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

15. माननीय अध्यक्ष महोदय! राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023–24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान

है, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की वृद्धि है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले नौ वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013–14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2022–23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा। इस तरह से 963 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत करवाते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया है।

अन्नदाता–किसान

16. माननीय अध्यक्ष महोदय! किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण, हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

17. सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2023–24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से है। बीज, उर्वरक और बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

18. मेरी फसल–मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के

लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य अंतर के आधार पर, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है।

19. पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी।

20. सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई–क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसान को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भू–स्वामियों को दी जाती थी। ई–क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।

21. वर्ष 2023–24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब–सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके

52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024–25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित बेकार और जलभराव वाली भूमि का अगले तीन वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

22. उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम 'दृश्या' के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है।

23. पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने में किसानों की सहायता करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और वर्ष 2023–24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई। वर्ष 2023–24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हो गए, जबकि 2021–22 में 6987 मामले दर्ज किए गए थे।

24. हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है और किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष

2023–24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

25. मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक, प्रशिक्षण, जर्मप्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए और चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

पशुपालन एवं डेयरी

26. माननीय अध्यक्ष महोदय! देश के 2.1 प्रतिशत दुधारू पशु हरियाणा में हैं, लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19 प्रतिशत से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.4 गुणा है।

27. पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

28. घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी।

29. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तीन मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घरद्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा।

सहकारिता

30. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार ने व्यापक बहुउद्देश्यीय गतिविधियाँ सहकारी समिति (सी.एम.–पैक्स) नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सी.एम.–पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण और परिवहन, भांडागार, बीमा और अन्य ग्रामीण–आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024–25 में 500 नए सी.एम.–पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सी.एम.–पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने–फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।

31. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जा रहे हैं। मैं 30 सितम्बर, 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा करता हूं, बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों। इससे किसान खरीफ–2024 सीजन के लिए पैक्स के माध्यम से फसली ऋण प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा।

32. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है और वर्ष 2023–24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन

के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.), रोहतक में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।

33. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि है।

गरीब और अंत्योदय

34. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र का विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो दिसम्बर, 2014 में 1000 रुपये मासिक थी। वर्ष 2013–14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था। यह वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़ाकर 10,971 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत है। लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है।

35. सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों को पेंशन देने की प्रक्रिया को प्रो–एक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्रियान्वित करके यह सुविधा लाभार्थियों के घरद्वार तक पहुंचाई है। प्रो–एक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है

और पिछले एक वर्ष में 5940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान भी की गई है। सरकार का अगले 3 महीनों में प्रो–एक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों की पेंशन और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

36. जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नहीं दिया जाता। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह से कम है। मैं ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रतिमाह या समय–समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए।

37. माननीय अध्यक्ष महोदय! पिछले साल अपने बजट भाषण में मैने घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह निर्माणाधीन है।

38. गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना पिछले साल शुरू की गई थी। यह योजना परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023–24 में अब

तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

39. माननीय अध्यक्ष महोदय! हमने एक योजना, डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले ऐसे सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है और जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक खपत पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रतिमाह तक है और वे दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है।

40. सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की पारिवारिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष तक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की हुई है। इसके तहत मेलों के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं।

41. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर–हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। वर्तमान में, 1,050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं, जिनमें से 686 दुकानें सरकार द्वारा दिए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं, जिनमें 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हर–हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है। मैं वर्ष

2024–25 में अतिरिक्त 1000 हर–हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं।

42. मुझे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई–टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

43. चिरायु–आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी. एम.– जे.ए.वाई) का लाभ नवंबर, 2022 में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। वर्तमान में, 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022–23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जबकि वर्ष 2023–24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम सभी गरीब परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करेगा।

44. माननीय अध्यक्ष महोदय! माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर में श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों

पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे यह वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे तथा इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम–सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

45. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता

46. माननीय अध्यक्ष महोदय! युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में, हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है।

47. 'मिशन 60,000' के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। फरवरी, 2024 में ठेकेदार

सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। यह योजना पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों में और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जी.एस.टी. पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें।

48. फरवरी, 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्‌देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर–वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1000 पौधों तक के संरक्षक के रूप में चार वर्ष कार्य करेगा ताकि ये पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरणीय स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी।

49. हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की हैं, जो नियुक्त कार्यबल में योगदान दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है।

50. हरियाणा कौशल रोजगार निगम सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी, 2024 में इजराइल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

51. यमुनानगर जिले के प्रताप नगर और पंचकुला जिले के कनौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। छह नई राजकीय आई.टी.आई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के मोहना, सेक्टर 18, सिकरोना और तिगांव, जिला महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 2024–25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.– सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार जिले के सिसाय, जींद जिले के पेगा, कुरूक्षेत्र जिले के शाहबाद एवं बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

52. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) के सहयोग से 'सुपर–30' उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य छह महीने के पाठ्यक्रम के लिए सघन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन व्यावसायिक विचारों और कौशल वाले 30 प्रतिभागियों का चयन करना है।

53. पिछले वर्ष मैने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्ट–अप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है। यह योजना वित्त वर्ष 2024–25 में चालू हो जाएगी।

54. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास

55. सरकार के तीसरे टीयर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फॉर्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एस.ओ.टी.आर.) के 7 प्रतिशत और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र–राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है।

56. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और पंचायती राज संस्थाएं उन्हें सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती हैं। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 2024–25 के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का है।

57. जिला परिषद्‌ों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप–केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

58. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि इन चौपालों का सही रख–रखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जन संवाद कार्यक्रमों में उठाई जा सकती है।

59. पिछले वर्ष ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए, सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है और मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खाते में सीधे जमा करवाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

60. माननीय अध्यक्ष महोदय! ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर–कम–वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गाँव स्वच्छ होंगे। वर्ष 2024–2025 में, मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं, जिनकी आबादी 7500 से अधिक है।

61. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं,

जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत की वृद्धि है।

शहरी विकास

62. पंचायती राज संस्थाओं की तरह, सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति आधार पर धन हस्तांतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 में, शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो नगर पालिकाएँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समय–समय पर अनुदान के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के माध्यम से व्यय के लिए वित्तीय परिव्यय के अतिरिक्त है, जिसमें वित्त वर्ष 2024–25 में 900 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

63. वित्त वर्ष 2023–24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नई नियमित की गई कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और वित्त वर्ष 2024–25 में विकास कार्यों में और तेजी आएगी। सरकार इन सभी कॉलोनियों में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले दो वर्षों में इन दायित्वों को पूरा करेगी। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024–25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

64. पीएम–स्वामित्व योजना की तर्ज पर, मैं नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी–स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम–स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी।

65. शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो–दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक–एक सभागार बनाए जाएंगे।

66. सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका के सहयोग से इन सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य किया जाएगा।

नगर एवं ग्राम आयोजना

67. बाहरी विकास शुल्क (ई.डी.सी.) की पुरानी लंबित देय राशियों की वसूली के लिए 'विवादों का समाधान' योजना शुरू की गई थी। यह योजना अत्यंत सफल रही है और इसमें 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई है। मैं इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि शेष लाइसेंसधारी भी योजना का लाभ उठा सकें।

68. महानगर विकास प्राधिकरणों की स्थापना की शुरूआत वर्ष 2017 में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद ऐसे तीन अन्य प्राधिकरण फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत में स्थापित किए गए हैं। हिसार महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

69. बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। सोनीपत और पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरणों ने हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि हिसार महानगर प्राधिकरण शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा। मैं सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100–100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ये राजस्व का स्थाई स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें।

70. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में शहरी क्षेत्र के लिए 5980.50 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत की वृद्धि है।

सभी के लिए आवास

71. माननीय अध्यक्ष महोदय! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) शुरू की है, जिसका उद्देश्य

उन परिवारों को आवास प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इसमें 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024–25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी। यह राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी।

72. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया है। मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपये तक की राशि का लाभ देगी ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद की जगह पर गांव में भूखंड खरीद सके।

73. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

खेल

74. माननीय अध्यक्ष महोदय! यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियों के आधार पर वर्ष 2023–24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए।

75. खेलो इंडिया पैरा गेम्स–2023 का आयोजन दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए किया गया। इन खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया।

76. मैं पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा, वित्त वर्ष 2024–25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2024–25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है।

77. स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। मैं राज्य में 6 स्थानों, अर्थात् करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं।

78. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.83 प्रतिशत की वृद्धि है।

शिक्षा

79. माननीय अध्यक्ष महोदय! नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत

आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण–अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। मैं शैक्षणिक सत्र 2024–25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं।

80. गुरुग्राम में फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कॉलेज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा।

81. सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई–लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। ई–पुस्तकालय छात्रों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।

82. सरकार ने 16 जनवरी, 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में लागू की जा रही है और इसका विस्तार अन्य खण्डों में भी किया जाएगा।

83. कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में 50 से अधिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

84. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार का प्रस्ताव है कि महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाए।

85. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वास्थ्य

86. माननीय अध्यक्ष महोदय! निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए हैं।

87. सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा वर्ष 2023 में प्रयोग के आधार पर दो विभागों के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। अब इसका विस्तार करके 1 जनवरी, 2024 से सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की जेब पर स्वास्थ्य–देखभाल के व्यय का भार कम करना है। इसके लिए अब तक 556 सूचीबद्ध अस्पतालों को शामिल किया गया है और 1340 उपचार पैकेजों को इस योजना के पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। यह सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा और उनके परिवार की स्वास्थ्य देखभाल लागत को वहन करने में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।

88. पिछले साल मैने चिरायु–आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपये का नाममात्र वार्षिक भुगतान करना होता है। मैं अब चिरायु–आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु–आयुष्मान भारत योजना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

89. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में निवारक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

90. वर्ष 2023–24 में पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक द्वारा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हरियाणा के मरीजों को लाभ होगा।

91. माननीय अध्यक्ष महोदय! आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम की ओर केन्द्रित करना चाहते हैं। इसके लिए वर्ष 2024–25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

92. पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में बाह्य रोगी देखभाल (ओ.पी.डी.) शुरू की है। इस संस्थान का निर्माण वर्ष 2024–25 में पूरा होने की उम्मीद है।

93. माननीय अध्यक्ष महोदय! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2024–25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद है।

94. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत की वृद्धि है।

नारी शक्ति

95. माननीय अध्यक्ष महोदय! सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और लोक प्रशासन में अत्यधिक योगदान दिया है।

96. ड्रोन पायलट प्रशिक्षण करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा (DRIISHYA) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मैं वर्ष 2024–25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक–एक ड्रोन देने का प्रस्ताव करता हूं। इसे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

97. मैने पिछले वर्ष पानीपत में तीज महोत्सव के दौरान प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांझा बाजार की स्थापना की घोषणा की थी। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन उपलब्ध करवाना है। जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है। सांझा बाजार में दुकानें स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। सांझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

98. हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 6.04 लाख महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया है। यह पहल स्थानीय उद्यमियों की सहायता करती है और समुदायों के भीतर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देती है। दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव है।

99. सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मांग कर 3224 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बाल विकास

100. सरकार बच्चों में कुपोषण को कम करने और उनकी वृद्धि व विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है।

101. वर्ष 2023–24 में, मैने अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है।

102. 'आपकी बेटी–हमारी बेटी' लड़कियों के लिए बनाई गई ऐसी योजना है जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की उपलब्धियों में मदद करती है। मैं इस योजना को परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के आंकड़ों के आधार पर प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाना सुनिश्चित कर सकेगी।

103. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत की वृद्धि है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

104. माननीय अध्यक्ष महोदय! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हो गई है। परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित और सक्रिय बना दिया गया है।

श्रम

105. 'हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 85,338 लाभार्थियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार ने हाल ही में ई–रुपे के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स–शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इससे निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

106. उबर, जोमैटो जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के लिए वस्तुओं और सेवाओं की घरद्वार पर डिलीवरी प्रदान करने वाले गिग वर्कर सेवा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरे हैं। ये आमतौर पर समाज के सबसे गरीब तबके के होते हैं। मैं एक ऐसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें गिग–वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान

पत्र तथा ई–श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वह ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

107. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत की वृद्धि है।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

108. हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिकों और सी.ए.पी.एफ. कर्मियों को उनकी सेवाओं और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों व हरियाणा के वासी हों।

109. सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

110. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वतंत्रता सेनानी

111. स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिये गये बलिदानों का सम्मान करते हुए, मैं उनका वर्तमान मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यावरण एवं वन

112. माननीय अध्यक्ष महोदय! स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने, इकॉलाजी में सुधार और पक्षियों व अन्य जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करने में मियावाकी पद्धति या सघन वृक्षारोपण अपनी प्रभावशीलता के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रही है। यह उन शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायी है, जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। मैं स्वदेशी, बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों पर बल देते हुए शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव करता हूं। आरंभ में, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा।

113. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत की वृद्धि है।

उद्योग

114. विकसित बुनियादी सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल जनशक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं से युक्त हरियाणा को सदैव एक औद्योगिक पावर हाउस माना गया है।

115. माननीय अध्यक्ष महोदय! जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से विकसित क्षेत्रों में से एक है। जैव प्रौद्योगिकी इको सिस्टम में अनुसंधान और विकास केंद्र, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और क्लस्टर्ड सामान्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। हरियाणा की भारत में जैव प्रौद्योगिकी पावरहाउस के रूप में उभरने की क्षमता है। मैं जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक जैव–प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

116. भारत वैश्विक **EV30@30** अभियान का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 शुरू की है। अब तक 12 योजनाओं को इस नीति के तहत अधिसूचित किया गया है।

117. हाल ही में ड्रोन प्रौद्योगिकी एक आधुनिक उद्योग के रूप में उभर रही है, कई क्षेत्रों में इसके उपयोग की पहचान की गई है। सरकार का मानना है कि ड्रोन निर्माण और ड्रोन आधारित इमेजिंग सेवाओं में हरियाणा को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मैं हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

118. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत की वृद्धि है।

अवसंरचना

गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण

119. माननीय अध्यक्ष महोदय! यह सत्य है कि ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए, सरकार ने इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए मानदंडों और मानकों की स्थापना व अधिसूचना तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की मान्यता के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन उपायों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा कठोर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षकों को सूचीबद्ध करने और मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने का कार्य भी करेगा।

सड़कें

120. माननीय अध्यक्ष महोदय ! वर्ष 2022–23 के बजट अभिभाषण के दौरान मैने घोषणा की थी कि लोक निर्माण विभाग के बजट की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर बजट की 64 प्रतिशत राशि का उपयोग करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, 216 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया है और 3057 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। मैं वर्ष 2024–25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024–25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।

121. 52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। वर्ष 2024–25 के दौरान

28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित है।

रेलवे अवसंरचना

122. माननीय अध्यक्ष महोदय! 61 किलोमीटर लम्बी करनाल–यमुनानगर रेलवे लाइन और 30 किलोमीटर लम्बी फर्रुखनगर–झज्जर रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है।

123. सरकार ने शहरी क्षेत्रों में यातायात की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कई उपरगामी पुलों के निर्माण के बजाय एलिवेटिड रेलवे ट्रैक की अवधारणा अपनाई है। इसके तहत एक परियोजना रोहतक शहर में चालू हो चुकी है। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024–25 में चालू होने की संभावना है। कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

124. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की आधारशिला अक्तूबर, 2022 में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा रखी गई थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली–मानेसर लाइन वर्ष 2024–25 में चालू होने की संभावना है।

125. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.76 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

126. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर

लिया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर और शहरी व अर्ध–शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है।

127. महाग्राम योजना के तहत 12 गांवों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने का काम पूरा हो चुका है तथा 31 मार्च, 2024 तक 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना है। शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाने की संभावना है।

128. 85 शहरों में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं और शेष काम इस वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है। मैं वर्ष 2024–25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं।

129. अमृत 2.0 के तहत सितंबर, 2023 में 48 पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं और 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन 57 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं का कार्य आवंटित किया गया है, जिनमें 18 जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 15 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं, जिनमें 10 जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं।

130. अमृत 2.0 के तहत, भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऊर्जा दक्ष मोटर–पंपों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने ऊर्जा दक्षता के लिए अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर–पंप स्थापित करने और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन आधारित सुधारों को अपनाने का प्रस्ताव किया है। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा।

131. सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा गैर–पीने योग्य उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने की नीति बनाई है। अब तक 199.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर–पीने के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा तथा गैर–पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। बहुमूल्य पानी के पुनः उपयोग से मीठे पानी की बचत होगी। सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ अधिसूचित किया है और कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

132. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सिंचाई एवं जल संसाधन

133. माननीय अध्यक्ष महोदय! ब्रिटिश शासन के समय से ही किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति पर आबियाना लगाया जाता रहा है। नहर के पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ–साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी।

134. राज्य सरकार नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023–24 के दौरान, जे.एल.एन. फीडर, हांसी ब्रांच, बालसमंद सब–ब्रांच, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, नारनौल ब्रांच,

कुराल डिस्ट्रीब्यूटरी, दीवाना डिस्ट्रीब्यूटरी, न्यू सिवानी फीडर, शेरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे प्रमुख चैनलों का सुधार सफलतापूर्वक किया गया है।

135. गैर–मानसून अवधि के दौरान पश्चिमी जमुना नहर वाहक प्रणाली को आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए 6000 क्यूसिक की क्षमता का एक नया समानांतर पक्का चैनल (PLC) वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, 465 करोड़ रुपये के निवेश से संवर्धन नहर और समानांतर दिल्ली ब्रांच की क्षमता में वृद्धि करने का काम चल रहा है।

136. माननीय अध्यक्ष महोदय! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक हो जाता है। थोड़े समय के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाएगा और पानी की कमी वाले जिलों–भिवानी, चरखी–दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा, राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन राजस्थान द्वारा बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त पानी को संग्रहीत किया जाए और कृषि व पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए और साथ–साथ बाढ की संभावना भी कम हो जाएगी।

137. गुरुग्राम और मेवात क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनमें गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रि–मॉडलिंग और मेवात फीडर पाइप लाइन परियोजना शामिल हैं। ये जिला नूंह, गुरुग्राम, मानेसर और बहादुरगढ़ शहरों तथा नए विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों–आई.एम.टी. मानेसर, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़ और

धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र तथा आसपास के गांवों की वर्ष 2050 तक की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। इनकी मौजूदा क्षमता 175 क्यूसिक से बढ़ाकर 686 क्यूसिक की जाएगी। इन दो परियोजनाओं पर 3028 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा यह कार्य अगस्त, 2024 तक शुरू होने की संभावना है।

138. मानसून के दौरान जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जल निकायों का निर्माण किया गया है और इन जल निकायों में पानी का संरक्षण किया गया है। इस बढ़ी हुई जल भंडारण क्षमता का अधिक सुसंगत और विश्वसनीय जल स्रोत के रूप में स्थानीय कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

139. यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर अप–स्ट्रीम भंडारण बांधों को पूरा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वर्ष 2023–24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं।

140. गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है और मैं वर्ष 2024–25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव करता हूं।

141. सरकार रावी–ब्यास नदी प्रणाली के पानी में हरियाणा के वैध हिस्से का उपयोग करने के लिए सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। एस.वाई.एल. के निर्माण के लम्बे समय से लंबित मामले के समाधान के लिए पंजाब और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए, मैं वर्ष 2024–25 के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

142. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत की वृद्धि है।

ऊर्जा

143. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार सभी के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा गांव–जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

144. गत वर्ष मैंने घोषणा की थी कि वर्ष 2023–24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट–हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बहरहाल, राज्य में वर्तमान में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। भविष्य में बिजली की मांग में अपेक्षित वृद्धि के दृष्टिगत इन पहलों से बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

145. बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उन उपभोक्ताओं पर मासिक न्यूनतम शुल्क (एम.एम.सी.) लगाया जाता है, जहां उनकी खपत एक सीमा से कम है। टैरिफ श्रेणी–1, जहां मासिक खपत 200 यूनिट तक है, में 2 किलोवाट तक मासिक न्यूनतम शुल्क 115 रुपये प्रति किलोवाट है। सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, मैं 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी–1 के उपभोक्ताओं के लिए

एम.एम.सी. को खत्म करने का प्रस्ताव करता हूं। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

146. गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।

147. मैंने वर्ष 2023–24 में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

148. माननीय अध्यक्ष महोदय! वर्ष 2023–24 में मैंने पी.एम. कुसुम के तहत 70,000 सौर पंप सेट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2023–24 से पहले निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना की लोकप्रियता और इसके प्रति किसानों के उत्साह को देखते हुए मैं वर्ष 2024–25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं।

149. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061.51 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

परिवहन

150. माननीय अध्यक्ष महोदय! मैने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि सरकार नौ शहरों में इलेक्ट्रिक बसों पर आधारित सिटी बस

सेवा शुरू करेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में ए.सी. इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी हैं और करनाल व पंचकुला में मार्च, 2024 के मध्य में शुरू हो जाएंगी। शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

151. लोगों की सुविधा और जीवनयापन को सुगम करने के लिए गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख बस अड्डों में यात्रियों की सुविधाओं, विशेषकर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

152. वित्त वर्ष 2024–25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदने की योजना है। इसके अलावा, सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आम जनता की सुविधा के लिए लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

153. ई–रिक्शा, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिंता और ई–रिक्शा मालिकों की मांग पर, मैं ई–रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी।

154. सरकार गैर–परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई–नीलामी की प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया में है। मुझे उम्मीद है कि मार्च, 2024 तक ई–नीलामी प्रक्रिया लागू

हो जाएगी। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होने के साथ–साथ नंबरों का आवंटन भी पारदर्शी आधार पर हो सकेगा।

नागरिक उड्डयन

155. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए कई पहल की हैं। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास, हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना इस समय अंतिम चरण में है और वर्ष 2024–25 के शुरुआत में उड़ान शुरू होने की संभावना है।

156. गुरुग्राम में हेली–हब शुरू करने का प्रस्ताव है। आठ जिलों नामतः जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। मैं नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। ई–भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024–25 में शुरू की जाएगी।

157. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 3,993.50 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वर्ष के 3,286.35 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि है।

पर्यटन और विरासत

158. माननीय अध्यक्ष महोदय ! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र यानि ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्‌घाटन 16 फरवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। यह केन्द्र 240 करोड़ रुपये की लागत से 17 एकड़ से अधिक

क्षेत्र में बनाया गया विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में से एक होगा।

159. मैने घोषणा की थी कि राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ सांझेदारी में गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया जा चुका है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। इसका कार्य वित्त वर्ष 2024–25 के अंत में शुरू होने की संभावना है।

160. पिछले साल नवम्बर माह में सरकार ने सुरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला स्थल पर मेले का आयोजन किया था। मेले के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, सरकार कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों व छोटे व्यवसायों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव करती है।

161. माननीय अध्यक्ष महोदय! भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधकर रखती है। मैं हरियाणा के जिलों में भारत के प्रत्येक राज्य की कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए उस राज्य की स्थापना तिथि के आसपास 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के तहत एक राज्य दिवस के अनुसार आयोजन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि हरियाणा के लोग भारत की विविधता को आत्मसात कर सकें।

162. हरियाणा में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो हमारे इतिहास और विरासत का हिस्सा हैं। भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखने की जरूरत है। संरक्षित स्थलों और स्मारकों के उचित संरक्षण व रख–रखाव सुनिश्चित करने

के लिए, मैं वित्त वर्ष 2024–25 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं।

163. अग्रोहा की पुरातात्विक खोजों और भारत की प्राचीन सभ्यताओं व विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

164. मैं वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242.43 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वर्ष के 165.37 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 46.59 प्रतिशत की वृद्धि है।

शासन और लोक प्रशासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

165. माननीय अध्यक्ष महोदय! जनवरी 2024 तक 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024–25 में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

भू–प्रबंधन

166. बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किसानों में असंतोष का कारण रही है। ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की स्वैच्छिक खरीद की नीति और लैंड पूलिंग और भूमि भागीदारी नीतियों की अधिसूचना से किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार माना जा रहा है। सरकार की मंशा ई–भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने की भी है।

गृह

167. माननीय अध्यक्ष महोदय ! मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) के कार्यान्वयन के संबंध में हरियाणा

पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस पूरे साल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रही और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया और 76.85 करोड़ रुपये बचाए।

168. हरियाणा सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मैं वर्ष 2024–25 में 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

169. प्रवर्तन कार्यों को मजबूत करने और अवैध खनन, नहर के पानी की चोरी, बिजली की चोरी, अवैध या नकली शराब की बिक्री जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक संस्थागत तंत्र को लागू करने के लिए पिछले साल हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में खनन और भूविज्ञान, आबकारी एवं कराधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, परिवहन, नगर एवं ग्राम आयोजन विभागों तथा शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

170. सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने ''हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी'' नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है। पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं का एक केंद्रीकृत डाटा बनाने, दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और संवेदनशील स्थानों

की पहचान करने के दृष्टिगत एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। 381 पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में और अधिक मदद मिलेगी।

171. घरौंडा में ग्राम पंचायत हसनपुर में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों तथा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है।

आबकारी एवं कराधान

172. माननीय अध्यक्ष महोदय! सरकार ने पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू.आर. कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू की है। डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है। यह निर्मित अल्कोहल की वास्तविक मात्रा को मापेगा। इससे सरकार शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर कड़ी नजर रख सकेगी।

173. जी.एस.टी. से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 1 जनवरी, 2024 से शुरू की गई है और यह 30 मार्च, 2024 को बंद हो जाएगी। इस योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना है।

174. सरकार का राज्य में नए स्टार्ट–अप करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2024–25 में गुरुग्राम में एक स्टार्ट–अप सुविधा सैल शुरू करने का प्रस्ताव है। यह सुविधा उन स्टार्टअप करदाताओं के लिए है, जिन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू कर दिए हैं या शुरू करने का इरादा रखते हैं। इस सुविधा से उन्हें जी.एस.टी. से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मदद और कर अनुकूल उपायों के बारे में जानकारी मिलेगी। सरकार का एम.एस.एम.ई.

क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पंचकुला में एक एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

खान एवं भूविज्ञान

175. माननीय अध्यक्ष महोदय! राज्य में खनन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए डिजिटलीकरण का उपयोग करने के दृष्टिकोण को जारी रखते हुए वर्ष 2023–24 में ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं।

176. मैंने घोषणा की थी कि वर्ष 2023–24 के दौरान एक नया संशोधित ई–रवाना पोर्टल चालू किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पुराने ई–रवाना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ''हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल'' नामक एक नया पोर्टल चालू कर दिया गया है। वेब्रिज को पोर्टल पर मैप किया जाता है और सिस्टम स्वचालित रूप से लोड किए गए वाहन के वजन के साथ वास्तविक समय में खनिज से भरे वाहनों की आवाजाही को कैप्चर करता है। इससे खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति

177. माननीय अध्यक्ष महोदय! यह गर्व की बात है कि निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हरियाणा ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया है और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

178. गत वर्ष मैंने घोषणा की थी कि गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए

खुशी हो रही है कि पिपली में गुरु रविदास स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और स्मारक का डिजाइन विशेषज्ञों व हितधारकों के परामर्श से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) द्वारा तैयार किया जा रहा है।

179. मैं सिखों के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और देश व मानवमात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए प्रस्तावित सिख संग्रहालय के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पिपली में जमीन देने की घोषणा करता हूं।

180. हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई थी ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, पटना साहिब, अजमेर शरीफ, वाराणसी, अमृतसर, उज्जैन, कटरा और नांदेड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सके। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक इन तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अयोध्या के तीर्थ यात्रियों का पहला समूह मार्च के पहले सप्ताह में रवाना होगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तीर्थ यात्रियों के समूह हर हफ्ते एक तीर्थ स्थल की यात्रा करने की योजना का लाभ उठाएंगे।

181. सरकार ने मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। गत वर्ष मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिसका पूरा प्रीमियम सरकार भरती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक संसाधन सूचना

182. माननीय अध्यक्ष महोदय! गुड गवर्नेंस या सुशासन ही इस सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस प्रयास के केंद्र में प्रौद्योगिकी आधारित अनूठा कार्यक्रम–परिवार पहचान पत्र है। परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य बगैर दस्तावेज और मानव हस्तक्षेप के प्रदेश के नागरिकों को घरद्वार पर सेवाएं प्रदान करना है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.60 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों ने अपना पंजीकरण कराया है। डेटा सत्यापन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं को अब परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है।

183. कुछ वर्ष पहले शुरू की गई सुशासन की पहल अब ऐसे चरण में है, जहां नागरिकों के जीवन में सुगमता के साथ–साथ ठोस लाभ दिखाई देने लगे हैं। आगामी वर्ष में, परिवार पहचान पत्र के तहत कुछ ऐसी पहल की जाएंगी ताकि अगले चरण में सरलता से प्रवेश किया जा सके।

184. सभी सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा पेश किए गए विविध ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों द्वारा जन सहायक ऐप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।

185. माननीय अध्यक्ष महोदय! मैने गत वर्ष कहा था कि सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपये के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि

योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। योजना के पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

186. राज्य सरकार ने ब्लॉक स्तर तक सरकारी कार्यालयों में बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ के उन्नयन के अलावा हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई है। इन कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना है।

निष्कर्ष

187. माननीय अध्यक्ष महोदय! यह वह समय है जब हमारा राष्ट्र बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि–''भारत के लिए, यही समय है, सही समय है'' राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र होगा। देश को एक विकसित भारत और हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए हम सब को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। यह वह अवधि है, जिसमें हमें अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करना है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनती लोग देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

188. हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने में हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें GYAN पर ध्यान देना होगा। GYAN मायने–गरीबों व अन्नदाता किसान को समुचित सुविधाएं प्रदान करना और युवाशक्ति व नारी शक्ति को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होगा।

189. माननीय अध्यक्ष महोदय! अमृत काल का यह बजट हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। मैंने बजट प्रस्तावों में फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति का विरोध किया है, क्योंकि राजकोषीय जिम्मेदारी और अनुशासन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भविष्य पर अनावश्यक बोझ न डालें। मुझे आशा है कि यह सदन सरकार के दृष्टिकोण को समझते हुए सहयोग व समर्थन करेगा।

190. मुझे यकीन है कि सदन में विचार—विमर्श से बजट समृद्ध और मजबूत होगा।

191. माननीय अध्यक्ष महोदय! इन शब्दों के साथ, मैं वर्ष 2024—25 के बजट प्रस्तावों को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द!

10890–F.D.–H.G.P.,Pkl.